जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 36 संख्याः 222 प्रभात अजमेर, रविवार 22 मार्च, 2026 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, ''प्रॉक्सी वॉर'' बना राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं के लिए

डोटासरा ने अभिषेक चौधरी को अपने उम्मीदवार के रूप में अपनाया है। डोटासरा के इस उम्मीदवार को पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चांदना का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मार्च। राजस्थान कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने समर्थक अभिषेक चौधरी के जरिए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में कदम रख दिया है।

यदि अभिषेक जीतते हैं, तो डोटासरा यह दिखा पाएंगे कि वे अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से आगे हैं और राजस्थान युवा कांग्रेस पर उनका नियंत्रण है।

डोटासरा ने कई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है और उम्मीद है कि उनके प्रभाव का इस्तेमाल कर अभिषेक के लिए वोट और समर्थन जुटाया जाएगा। पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चांदना ने भी डोटासरा का समर्थन किया है।

दिलचस्प बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे

- अशोक गहलोत की यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अभी तक नगण्य सी भूमिका है।
- सचिन पायलट ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पर, बाकी गंभीर उम्मीदवार, अनिल चोपड़ा, मुकुल खींचड़ अपने आप को सचिन पायलट का उम्मीदवार होना बता रहे हैं। सीकर के राजकुमार परसवाल भी उम्मीदवार हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि सीकर के वरिष्ठ नेता सीताराम लाम्बा के मार्फत गहलोत, परसवाल को अपना उम्मीदवार जता रहे हैं।
- ऐसा माना जा रहा है कि डोटासरा अपने उम्मीदवार अभिषेक को जितवाकर आगामी विधानसभा चुनाव की ज़मीन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यह आम धारणा है कि जो व्यक्ति यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पर अपना नियंत्रण दिखा सकेगा, वह कांग्रेस की प्रदेश की भावी राजनीति पर अपना शिकंजा कस सकेगा। डोटासरा अभिषेक चौधरी को जितवाकर यह साबित करना चाहते हैं कि वे गहलोत व पायलट के समकक्ष नेता हो गए हैं, क्योंकि युवा शक्ति उनके साथ है।

घटनाक्रम में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। कोई भी उम्मीदवार गहलोत का समर्थन हासिल करने की कोशिश करता नहीं दिख रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत का प्रभाव अब कम हो गया है, क्योंकि उनके कई करीबी नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं।

वहीं, सचिन पायलट ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि अटकलें हैं कि चुनाव लड़ने वाले तीन संभावित उम्मीदवार उनके खेमे से हो सकते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्यों को 20 प्रतिशत ज्यादा एलपीजी मिलेगी

नई दिल्ली, 21 मार्च। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को बड़ी राहत दी है। इस संबंध में मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 23 मार्च 2026 से राज्यों को अब पहले के मुकाबले 20 प्रतिशत ज्यादा गैस दी जाएगी।

यह जो अतिरिक्त 20 प्रतिशत गैस दी जाएगी, उसका प्रयोग चुने गए

- एलपीजी संकट के बीच केन्द्र सरकार ने नई व्यवस्था घोषित की, जो 23 मार्च से लागू होगी।

सेक्टरों के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। डॉ. नीरज मित्तल के पत्र के मुताबिक, यह सप्लाई मुख्य रूप से ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्रियल कैंटीन को दी जाएगी। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खान-पान की सेवाओं और फूड इंडस्ट्री पर संकट का असर कम से कम से कम हो।

प्रवासी मजदूरों की जरूरतों का भी मंत्रालय ने ध्यान रखा है। पत्र के मुताबिक 5 किलो वाले फ्री ट्रेड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर अमेरिकी ''बेस'' डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया

हालांकि, इस मिसाइल हमले से ''एयर बेस'' को क्षति नहीं पहुंची, पर, खाड़ी युद्ध का आयाम बदल गया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मार्च। ईरान ने अमेरिका-इज़रायल गठबंधन के साथ चल रहे युद्ध को पश्चिम एशिया से बहुत दूर, करीब 4,000 किलोमीटर दूर, हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप तक फैला दिया है। ईरान की मिसाइलों की इतनी लंबी मारक क्षमता ने पश्चिम के सैन्य हलकों को चौंका दिया है और रणनीतिक विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है

अब तक माना जाता था कि ईरान के पास 1250-1300 किलोमीटर तक मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइलें ही हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता को छिपाकर रखा था और इनके बारे में कम जानकारी दी थी।

ब्रिटेन ने हाल ही में अमेरिका को चागोस द्वीप समूह के डिएगो गार्सिया स्थित अपने एयरबेस का उपयोग ईरान पर हमले के लिए करने की अनुमति दी थी। इसके जवाब में ईरान ने इस एयरबेस को निशाना बनाकर अपनी मिसाइल शक्ति दिखाने की कोशिश की। हालांकि, ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक

- हालांकि, अमेरिका अभी भी अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आया तथा दावा करता रहा है कि ईरान पर विजय हासिल कर ली है, अतः अब युद्ध को ठंडा करना शुरु करेगा।
- पर, सच्चाई यह प्रतीत होती है कि बेबस अमेरिका अब किसी भी तरह खाड़ी युद्ध से भागना चाहता है।
- एक तरफ तो ईरान की मिसाइल की मार इतनी दूर तक होना तथा अमेरिका के आधुनिक लड़ाकू विमान एफ-16 को ईरान द्वारा गिराने से अमेरिका ने ईरान की तरफ अपना रूख भी ढीला किया तथा ईरान को अपना तेल बेचने की ''इजाज़त'' दी। इस तरह ईरान का 140 मिलियन बैरल ऑयल, जिसकी कीमत लगभग 14 बिलियन डॉलन आंकी जाती है, अब बिक्री के लिए बाज़ार में आ गया है।
- झेंप मिटाने के लिए अमेरिका अब यह भी कह रहा है कि उसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रास्ते से एशिया व चीन का तेल आता है, अमेरिका का नहीं। पर, फिर भी वह आसानी से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुलवा सकता है, अगर कुछ देश उसका साथ दें।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने यूएनआई से दिल्ली मुख्यालय छीना

हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने पत्रकारों को मुख्यालय से बाहर निकाला

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मार्च। पुलिस ने वकीलों और अधिकारियों के साथ शुक्रवार रात यहां यूएनआई समाचार एजेंसी के मुख्यालय को सील कर दिया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे सरकारी जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया। पत्रकारों को उस समय बाहर निकाल दिया गया, जब उनका काम का बहुत तेजी पर था।

अदालत ने कहा कि यूएनआई 45 वर्षों से अधिक समय तक इस मूल्यवान सार्वजनिक भूमि पर प्रभावी रुप से कब्जा जमाए हुए थी, जबकि वह भूमि आवंटन की शर्तों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ रही।

पुलिस की यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेन्ट्रल दिल्ली में, कनॉट प्लेस से कुछ ही दूरी पर स्थित, चार दशक पहले यूएनआई को

- जिस समय यह कार्यवाही हुई, उस समय पत्रकार काम में बहुत व्यस्त थे। ज्ञातव्य है कि इस ऑफिस से अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू की न्यूज़ एजेंसीज़ काम करती हैं।
- हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यूएनआई ने 45 साल से कीमती सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और आवंटन की शर्तों का पालन भी नहीं किया है, इसलिए यह भूखंड तुरंत वापस लिया जाए।
- भूमि विकास कार्यालय ने 29 मार्च को सैंट्रल दिल्ली के, 9, रफी मार्ग स्थित 2024 वर्ग मीटर के भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया था। यूएनआई ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी, पर हाई कोर्ट ने यूएनआई की याचिका खारिज कर दी।

दी गई भूमि के आवंटन को रद्द करने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे यह आदेश पारित किया और यूएनआई की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने 29 मार्च 2023 के भूमि एवं विकास कार्यालय के पत्र को चुनौती दी थी। इस पत्र में सेन्ट्रल दिल्ली के रफी मार्ग स्थित 2,024 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन को रद्द किया गया था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन किया

नई दिल्ली, 21 मार्च। पश्चिम एशिया में पिछले 22 दिनों से जारी सैन्य संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन से शनिवार को टेलीफोन कर बातचीत की और ईद एवं नवरोज़ की बधाई दी। मोदी

- प्र.मंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन को ईद व नवरोज़ की शुभकानाएं दीं, पश्चिम एशिया शांति स्थापना के लिए वार्ता की।

ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहारों का मौसम पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हालिया हमलों पर चिंता जताई और उनकी कड़ी निंदा की।

प्रधानमंत्री ने नौवहन की स्वतंत्रता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीतीश के बेटे निशांत होंगे जद (यू) के वर्किंग प्रैसिडैंट

नीतीश सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बनाने के संकेत पहले ही दे चुके हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मार्च। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां अपने उत्तराधिकारी के रूप में भाजपा के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर अपनी पसंद का संकेत साफ तौर पर दिया है, वहीं इस वरिष्ठ समाजवादी नेता ने वंशवादी राजनीति के प्रति अपना विरोध भी छोड़ दिया है, क्योंकि वे परोक्ष रूप से अपने बेटे निशांत कुमार को राज्य की राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार लगभग दो दशकों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, 9 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने से पहले, अर्थात अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।

कुमार, अपने गिरते मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रिपोर्टों के बावजूद, फिलहाल सक्रिय राजनीति छोड़ने के इच्छुक नहीं दिखते। वे चौथी बार भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे, और ऐसे भी साफ संकेत हैं कि वे अपने बेटे निशांत के लिए कोई महत्वपूर्ण पद चाहते हैं।

सूत्रों के अनुसार, निशांत को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तथा इस प्रकार वे संजय कुमार झा की जगह ले सकते हैं। इस पद के खाली होने की संभावना भी है। दरअसल हरिवंश नारायण सिंह का राज्यसभा कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और चूंकि हरिवंश को दोबारा नामित नहीं किया गया है, इसलिए ऐसे संकेत हैं कि संजय कुमार झा को इस पद पर पदोन्नत किया जा सकता है।

- दो दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार 9 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे और इससे पहले वे संभवतया बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे।
- नीतीश के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लगातार बिगड़ने की खबरों के बावजूद भी वे सक्रिय राजनीति में बने रहना चाहते हैं और जद (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे।
- निशांत के वर्किंग प्रैसिडैंट बनने से संजय झा को यह पद छोड़ना पड़ेगा और चर्चा है कि उन्हें राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह के पद पर एडजस्ट किया जा सकता है। हरिवंश को इस बार राज्यसभा का टिकट नहीं मिला है।

नीतीश कुमार को रविवार को औपचारिक रूप से जदयू का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किए जाने की संभावना है, क्योंकि इस पद के लिये नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि कल है।

हालांकि जदयू के कुछ नेताओं द्वारा निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी, लेकिन यह माँग कुछ ज्यादा ही बड़ी मानी जा रही थी। हालाँकि ऐसे पर्याप्त संकेत हैं कि उन्हें बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है। यह भी संभावना है कि उन्हें बिहार की नई कैबिनेट में उपमुख्यमंत्री बना दिया जाये।

निशांत भी इस दिशा में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे हाल ही में जहानाबाद गए थे, जहां उन्होंने पूर्व सांसद अरुण कुमार और जदयू विधायक ऋतुराज

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने ईद की शुभकानाएं दी

नई दिल्ली, 21 मार्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को ईद-उल-फितर के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए समाज में

- तीनों नेताओं ने एक्स पर लिखी अलग-अलग पोस्ट समाज में भाईचारे, शांति व सद्भाव की कामना की।

भाईचारा, सद्भाव एवं खुशहाली की कामना की।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि ईद-उल-फितर के पावन अवसर पर सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को हार्दिक बधाई।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

साउथ पार्स में आग लगी तो भारत की इकॉनमी भी झुलसेगी?

फारस की खाड़ी में स्थित साउथ पार्स विश्व का सबसे बड़ा गैस फील्ड है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मार्च। पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज होने के साथ, फारस की खाड़ी में स्थित एक सुदूर गैस क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक शांत, लेकिन गंभीर चिंता बनकर उभर रहा है। साउथ पार्स, कतर के नॉर्थ फील्ड के साथ साझा एक विशाल समुद्री गैस भंडार का ईरानी हिस्सा है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि भले ही भारत सीधे ईरान से गैस नहीं खरीदता, लेकिन इसके आसपास का क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय एलएनजी व्यापार के केन्द्र में है। यहां उत्पादन, शिपिंग या निवेशकों के भरोसे पर कोई भी खतरा जल्दी ही भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग और घरेलू बजट को प्रभावित कर सकता है।

भारत के लिए तत्काल खतरा गैस की आपूर्ति रुकने का नहीं, बल्कि कीमतों में तीव्र बढ़ोतरी का है। कतर, जिसका नॉर्थ फील्ड इसी बड़े भंडार का हिस्सा है, सन् 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक था और वैश्विक एलएनजी निर्यात का लगभग पांचवां हिस्सा कतर ही देता था। कतर का लगभग पूरा एलएनजी होर्मुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) से होकर गुजरता है, जहां से 2025 में दुनिया के कुल एलएनजी व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत (करीब 112 अरब घन मीटर) गुजरता था। इससे साफ है कि साउथ पार्स, नॉर्थ फील्ड क्षेत्र केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय गैस व्यापार का केन्द्र है।

भारत के लिए इसका मतलब यह है कि एलएनजी की बढ़ती कीमतें सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगी। इसका

- इसके बड़े हिस्से पर ईरान का कब्जा है और कतर का नॉर्थ फील्ड भी इसी से सटा हुआ है। खाड़ी युद्ध में अमेरिका-इज़रायल ने इस गैस फील्ड को निशाना बनाने की धमकी दी है।
- इस क्षेत्र पर हमले से पूरे विश्व में लिक्विफाइड नैचुरल गैस (एलएनजी) की आपूर्ति प्रभावित हो जाएगी। यह क्षेत्र एलएनजी व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र है।
- भारत, एलएनजी के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है और अगर साउथ पार्स पर हमला हुआ तो भारत में एलएनजी के दाम आसमान छूने लगेंगे और यह भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेल सकता है।

असर उर्वरक की लागत, शहरों में गैस वितरण, उद्योगों के ईंधन खर्च और अंत में महंगाई पर पड़ेगा। भारत पहले से ही आयातित तेल और गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर है, और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश की ऊर्जा व्यवस्था में इनका कितना बड़ा महत्व है। भले ही गैस की सप्लाई जारी रहे, लेकिन युद्ध का जोखिम, बीमा लागत और बाजार में अटकलें भारत के आयात बिल को बढ़ा सकती हैं।

समस्या का एक और पहलू है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, 2025 में होर्मुज़ से गुजरने वाले एलएनजी का लगभग 90 प्रतिशत एशिया जा रहा था। यानी, सबसे पहले असर एशिया पर पड़ता है और भारत भी उसी दबाव वाले क्षेत्र में आता है। अगर खाड़ी के समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ता है, तो भारत को न केवल ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि अन्य एशियाई देशों के साथ गैस खरीदने की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है। खासकर ऐसे बाज़ार में, जहां वास्तविक आपूर्ति रुकने से पहले ही कीमतें तेजी से बदलने लगती हैं।

साउथ पार्स इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ईरान की अपनी गैस व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार, इस क्षेत्र से होने वाला उत्पादन ईरान की घरेलू जरूरतों और निर्यात, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए भले ही संघर्ष सीधे एलएनजी व्यापार को न रोके, लेकिन साउथ पार्स के आसपास अस्थिरता पूरे क्षेत्र में ऊर्जा को लेकर चिंता बढ़ा सकती है। बाज़ार सिर्फ आपूर्ति में कमी पर नहीं, बल्कि संभावित जोखिम के डर पर भी प्रतिक्रिया देता है

नई दिल्ली के लिए इसका साफ सबक है। युद्ध प्रभावित खाड़ी क्षेत्र में भारत की कमज़ोरी केवल तेल तक सीमित नहीं रही। अब गैस, समुद्री रास्ते और आयातित ऊर्जा की लागत भी उतनी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद नहीं किया है'

तेहरान, 21 मार्च। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान ने स्पष्ट किया है कि उसने रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद नहीं किया है, बल्कि केवल कुछ चुनिंदा जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाए हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराघची के इस बयान ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़

- ईरान के विदेश मंत्री ने जापानी न्यूज़ एजेंसी को दिए इन्टरव्यु में कहा हम अपने सहयोगी देशों को रास्ता देने व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं।

ती चिंताओं के बीच स्थिति को लेकर नया स्पष्टीकरण दिया।

ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार जापान की क्योदो न्यूज़ एजेंसी को दिए इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट खुला है और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)